AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Prime Minister had announced at Cuddapah during his visit to Andhra Pradesh recently that the centre would henceforth route the subsidised rice for tribals through panchayats;

(b) if so, the details thereof and reasons therefor;

(c) by when it is being implemented; and

(d) whether this announcement is also applicable to all the States?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD AND **CIVIL** SUPPLIES (SHRI SUKH RAM): (a) to (d) The Prime Minister had made a general observation to this effect and the matter is under the consideration of the Government.

**Welfare activities for Beedi Workers**

**456.** SHRI K. V. THANGKA-**BALU** : Will the Minister of **LA-BOUR** be pleased to state :

(a) whether Government propose to promote welfare activities for the beedi workers in the country as reported in the Hindustan Times dated 22nd May, 1989 ; and

(b) if so, what are the details in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RA-DHAKRISHAN MALAVIYA) : (a) and (b) Under the Beedi Workers Welfare Fund, welfare schemes for health, housing, education, recreation and family welfare are extended to nearly 32.75 lakh beedi workers in the country. At present, **154** dispensaries, a 10-bedded hospital and a Chest Clinic are functioning to provide free medical treatment to beedi workers and their families. Administrative approval has been issued for setting up hospitals at Murshidabad (West Bengal), Mukkadal (Tamil Nadu), Guisahaiganj (Uttar Pradesh) and for .upgradatic n of the 10-bedded hospital at Mysore (Kar-nataka) to 50-bedded. Financial assistance for construction of houses is provided to State Governments and also to beedi workers under different schemes. Scholarships are awarded to wards of beedi workers.

During 1988-89, a sum of Rs. 6.60 crores, approximately, was spent on welfare of beedi workers. The Budget Estimates of 1989-90 have provided for Rs. 15.11 crores which includes Rs. 6.98 crores on health, Rs. 5.11 crores on housing and Rs. 1.59 crores on education.

**अनुसूचित/जन जातियों की सूची में "कोल" समुदाय को शामिल न किया जाना**

**457. श्री सत्य प्रकाश मालवीय-** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में "कोल" समुदाय के व्यक्तियों को अभी तक अनुसूचित जनजातियों में शामिल नहीं किया गया है ; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें "कोल" समुदाय के व्यक्तियों को अनुसूचित जनजातियों में शामिल कर लिया गया है ; और

(ग) उत्तर प्रदेश में उक्त समुदाय के व्यक्तियों को कब तक अनुसूचित जनजातियों में शामिल कर लिया जायेगा ?

**कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा. राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी)** : (क) से (ग) कोल समुदाय को, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की सूची में, तथा

मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा राज्यों में अनुसूचित जन जातियों की सूचियों में शामिल किया गया है प्रत्येक राज्य के लिये, किसी भी समुदाय को शामिल करने का निर्णय अलग-अलग उस राज्य के लिये प्रासंगिकता पर विचार करके ही लिया जाता है । संविधान के अनुच्छेद 341 (2) तथा 342(2) के अन्तर्गत बनाये गये प्रावधानों को ध्यान में रखते हुये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों की वर्तमान सूचियों में किन्हीं युक्तियुक्त कारणों से, कोई भी संशोधन केवल संसद के अधिनियम द्वारा ही किया जा सकता है । इस संबंध में किसी समय सीमा का उल्लेख नहीं किया जा सकता ।

**मंडल आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन**

458. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या कल्याण मंत्री 5 मई, 1989 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 1330 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछड़े वर्गों के संबंध में मंडल आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को लागू करने में सरकार के सामने क्या-क्या कठिनाईयां पेश आ रही हैं ; और

(ख) इस संबंध में राष्ट्रीय सर्वेक्ष प्राप्त करने के लिये सरकार क्या-क्या कदम उठा रही है ?

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा. राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी) : (क) मंडल आयोग की सिफारिशों पर चूंकि कोई निर्णय नहीं हुआ है, अतः इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने अथवा इनमें कठिनाइयों का सामना किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ख) यद्यपि विभिन्न स्तर पर विभिन्न मंचों पर चर्चाएं हुई हैं, तथापि राष्ट्रीय स्तर पर कोई सर्वेक्षण किसी समय में ही विचाराधीन हो सकता है । इसी बीच सरकार द्वारा गरीबी कम करने और व्यापक साक्षरता की योजनायें तथा समाज के गरीब और पिछड़े वर्गों के समाजार्थिक विकास के उपायों को पूरे जोर से लागू किया जा रहा है ।

**Bonded labour in the country**

459. SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK : Will the Minister of LABOUR be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large number of bonded Labourers are still working in the country;

(b) if so, number of bonded labourers at present in each State; and

(c) what step/action are taken by Government to get them free ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RA-DHAKRISHAN MALAVIYA) : (a) According to the information received from the State Gov's., *the* total number of bonded labourers identified in the various States as on 31st March, 1989 was 2,42,532 and the numb;-r of those rehabilitated by that date was 2,17,816.

(b) A Statement prepared on the basis of the information received from the Slate Governments showing the number of Bond d Labourers identified and rehabilitated in each of the Slates as on 31st March, 1989 is attached. *(See* below)

(c) Under 'he Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976, *the* responsibility for identification, re-lease and. rehabilitation of bonded labour lies with the concerned Slate Governments. It is the statutory obligation of the State Govts, to get a bonded labourer freed as soon as he is identified in the State.